

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,  
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 12 दिसम्बर, 2007

विषय :- एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थानों से पत्राचार बी0एड0 उपाधिधारक अभ्यर्थियों के विशिष्ट बी.टी.सी. हेतु चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बेसिक/48997/ वि0बी0टी0सी0/2007-08 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 में उल्लिखित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

1. विशिष्ट बी0टी0सी0 हेतु वर्ष 2007-08 में जनपदवार सभी 13 जनपदों में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2006-07 प्रारम्भ करने के लिये जनपदवार कुल 4956 सीटें स्वीकृत की गयी, जिनकी संख्या बढ़ाने अथवा घटाने का भी प्राविधान किया गया। शासनादेश दिनांक 13.6.2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदवार आंवटित सीटों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित करने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 09 जुलाई, 2006 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई।
2. विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय/संस्थान से एल0टी0/बी0एड0/ बी0पी0एड0/ डी0पी0एड0/सी0पी0एड0(सीपीएड वर्ष 1996-97 से पूर्व) तथा मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्री की उपाधि संस्थागत छात्र के रूप में प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई। इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य किया गया।
3. अतः विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण के लिये चयन हेतु केवल संस्थागत रूप में बी.एड. उपाधिधारक अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिये पात्र थे।
4. विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त पत्राचार के माध्यम से कतिपय बी.एड. उपाधिधारक अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट

याचिकायें योजित की गई, जिनपर मा० उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किये गये कि :-

“पत्राचार के माध्यम से बी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में अन्तिम आदेश पारित होने तक चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाय, किन्तु इन अभ्यर्थियों का चयन मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा।”

5. मा० उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-884/XXIV(1)/2006-45/2004 दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा पत्राचार के माध्यम से बी.एड. उपाधि प्राप्त की गई थी, को विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने के लिये समान अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई।

6. विशिष्ट बी०टी०सी० चयन हेतु शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्रों द्वारा माह जून-जुलाई, 2007 में मैरिट लिस्ट तैयार की गई। मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में पत्राचार के माध्यम से बी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी मैरिट लिस्ट में सम्मिलित किया गया। किन्तु उनके नाम के आगे निम्न उल्लेख किया गया :-

“इन अभ्यर्थियों का चयन मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अधीन रहेगा।”

7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा पत्राचार के माध्यम से बी०एड० बी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये दिनांक 19 जुलाई, 2007 को अन्तिम आदेश पारित करते हुये ऐसी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

8. पत्राचार के माध्यम से बी०एड० प्रशिक्षित लगभग 564 अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये तैयार की गई मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया गया। पौड़ी जनपद में पत्राचार के माध्यम से बी०एड० प्रशिक्षित 54 अभ्यर्थियों को मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय प्राप्त होने से पूर्व ही प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित करने विषयक पत्र निर्गत कर दिया गया था। जिसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि उनका चयन मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा। शेष जनपदों में पत्राचार के माध्यम से बी०एड० करने वाले अभ्यर्थियों को मा० उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण हेतु चयन पत्र निर्गत नहीं किया गया।

9. मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2007 के क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या/बाद/20632-78/2007-08 दिनांक 01 अगस्त, 2007 द्वारा विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु सभी पत्राचार बी.एड. उपाधिधारक अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त कर दिया गया।



10. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2007 से व्यथित होकर पत्राचार के माध्यम से बी.एड. प्रशिक्षित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय की डबल बेंच के समक्ष विशेष अपील संख्या 117/2007 योजित की गई। मा0 उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा सम्बन्धित याचिका में पारित निर्णय दिनांक 20-11-2007 के प्रस्तर 4 एवं 5 में निम्न आदेश पारित किये गये :-

(4) "In our opinion, it would be appropriate and in the interest of justice that the State Government is permitted to take an independent decision in the matter considering the dimension of the unemployment problem in the State within a period of two weeks. A copy of the decision to be taken by the State Government in the matter be produced for our perusal on the next date of hearing."

(5) "We, further, deem it proper to observe that the State Government shall take decision in the matter without being influenced by any of the observations made in the impugned judgment and the fact of the pendency of these Special Appeals and the dismissal of Special Appeal No. 101 of 2007."

11. विचारणीय है कि वर्तमान प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 को ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से बी.एड. उपाधि प्राप्त की थी, को विशिष्ट बी.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु समान अवसर दिये जाने के दृष्टिकोण से आवेदन करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, तदुपरान्त ही वर्षवार मेरिट के आधार पर चयन किया गया तथा कुछ पत्राचार बी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को चयनित करके प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना भी कर दी गई।

12. अतः मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.11.2007 के आलोक में आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट बी0टी0सी0 हेतु वर्ष 2007-08 में जनपदवार आवंटित सीटों के सापेक्ष मैरिट सूची में चयन हेतु स्थान पाने वाले संस्थागत अभ्यर्थियों को प्रभावित किये बिना, मैरिट सूची में चयन हेतु स्थान प्राप्त करने वाले पत्राचार माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिये अतिरिक्त व्यवस्था कराते हुये, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मात्र इस वर्ष (2007-08) के लिये चयनित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

13. भविष्य में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं चयन के लिये समग्र रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त नीति निर्धारित कर निर्णय लिया जायेगा।

14. राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को विशिष्ट बी०टी०सी० से भरे जाने विषयक शासनादेश संख्या-448/XXIV(1)/2006-45/2004 दिनांक 13 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-884/XXIV(1)/2006-45/2004 दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 को इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,


(हरिश्चन्द्र जोशी)  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. अपर शिक्षा निदेशक/संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य डायट उत्तराखण्ड (निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के माध्यम से)
7. एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

  
(डा० भूपिन्दर कौर)  
अपर सचिव।